

फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य : धामी

देहरादून, 25 जुलाई (जन्सता)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में उत्तराखंडी फीचर फिल्म 'पहाड़ी रथ श्रौच्य सुमन' की शहकारी तथा पेशेवर का निर्माण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। राज्य में फिल्मकारों के लिए रूपायत फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

'कांडा' ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खुदकुशी के लिए उकसाने वाला कोई काम नहीं किया'

जन्सता ब्यूरो नई दिल्ली, 25 जुलाई।

दिल्ली को एक अदालत ने धामन परिचायिका गौतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए कांडा तौर पर उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कुमार कांडा को मंगलवार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि कांडा ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं किया जिससे उनकी विधामन कथनों में काम करने वाली शर्मा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई।

अदालत ने कहा कि कांडा यास्वत में शर्मा के प्रति आकर्षित थे, जो उसे उनको कर्मीयों में ची गई प्योनीति और उसे दिए गए उम्दाओं से स्पष्ट बना है। विशेष न्यायायांश विवाह दूत ने माना कि अधिभोजन पर इन आरोपों को साक्षित करने में अफारल राहा कि आध्यायिक साक्षर के तहत शर्मा परिचायिका पौर को गई न्यायिक कारण शर्मा के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प न था। न्यायाधीश ने 189 पानों के फैसले में कहा कि 'भले ही अधिभोजन पक्ष के गवाह यह बयान देकर 'पारत जाति' की कोशिश कर रहे थे कि शर्मा ने तीन आशर, 2012 की रात मुम्बई पहुंचे अंड्रे पर विवाहित थी, लेकिन इस बात को प्रचल संभावना की कि यह किसी अन्य व्यक्ति के साथ मुम्बई में करी थी, जिसके साथ उसके शारीरिक संबंध थे।' न्यायाधीश ने कहा कि शर्मा की मौत से पहले उसके किसी तरह के शारीरिक संबंध होने की बात उसकी पेशकश रिपोर्ट से स्पष्ट होती है। न्यायाधीश ने कहा, 'इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चूना और कांडा ने क्रमशः तीन और बार आशर, 2012 को टेलीफोन पर बातचीत में शर्मा को ना के समक्ष परिवार के शुभचिंतकों को भी इम्भावित इस तथ्य का खुलासा किया जिसके कारण बार आशर, 2012 को मुम्बई से लौटने पर शर्मा और उसकी मा के बीच झगडा हुआ और उसके बाद शर्मा ने शर्मा ने आत्महत्या कर ली।' न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि शर्मा ने 'सुराहद नोट' में अफारल कहा कि उसने आरोपियों पर शरीर करके अपने जीवन की सहाई मालती को ही, यह आरोपी व्यक्तियों द्वारा उकसाए गए तौर पर आशर, 2012 को मुम्बई में रुकने के बारे में जायकारी साक्षा करके उसके विश्वास को तोड़ने के संबंध में ही सकता है।'

गौतिका के भाई ने पूछा, 1800 पृष्ठ के आरोपपत्र में कैसे नहीं मिला सबूत

नई दिल्ली, 25 जुलाई (ब्यूरो)।

धामन परिचायिका गौतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को दिल्ली को एक अदालत द्वारा बरी कर दिया जाने के बाद 11 साल से 'भानानसक कंधा' का सामना कर रहा शर्मा का परिवार दुःख ग्वा है। गौतिका शर्मा के भाई अशिका शर्मा ने मंगलवार को यह बात कही। अशिका ने कहा, '66 साल के मेरे पिता फैसला करने के बाद से लय्य है।'

उन्होंने कहा कि उनके पाप गुरुका लड़ने के लिए सामन नहीं है और सरकारी को आंशर के खिलाफ आरोप धारण करनी चाहिए। अशिका ने दावा किया कि उनका जमाना को खतरा है। 'सुराहद नोट' में गौतिका शर्मा ने कहा था कि वह कांडा और अरणा चूका के 'उत्पीठन' से ना आकर आत्महत्या कर रही है। नगरपाली नाती कांडा को उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद यह राज्यमंत्री के पर से इतलीक नाती पडा था। गौतिका के आत्महत्या करने के छह महीने बाद उनकी मौत भी खुदकुशी कर ली थी। अशिका ने अपने पत्र कहा, 'हमारे लिए 11 वष भवानसक रूप से अत्यंत-पुखर रहे हैं।'

वह 11 सालों की लोके लुका का अंशम है। हम उन अपने जमान को लेकर डरे हुए हैं। यह हमारे लिए जालेक सिद्ध है।' विशेष न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि अधिभोजन पक्ष शर्मा उचित संकेतों से पर आरोपों को साक्षित करने में नाकाम रहा। अशिका ने आरोप लगाया कि कांडा के 'प्रभाव' ने उसके मरद की उम्दीक कहा, 'मेरा कंधा है कि 1800 पृष्ठ के आरोपपत्र में कोई सबूत नहीं था।' गौतिका शर्मा ने काम करने वाले उम्दीक ने कहा, 'सभी आरोप प्रदात किए गए - आउटी एड, जालायां, आत्महत्या के लिए उकसाया। ऐसे संकेत भी थे जिनसे यह स्पष्ट है कि कांडा ने शर्मा का कोई परभाव किया था। अगर सबूतों का अभाव था तो अदालत ने साक्ष के आश्रय नहीं दिए?'

मेघालय : मुख्यमंत्री सचिवालय पर हमला पूर्व नियोजित, सप्तामा को नुकसान पहुंचाने की थी साजिश : डीजीपी

शिलांग, 25 जुलाई (एजेंसी)।

मेघालय के पुलिस प्रमुख एच.आर. धर्मवंत ने मंगलवार को बताया कि दूत में मुख्यमंत्री कार्यालय पर 24 जुलाई को हुए हमले का पीछा किया गया प्रस्ता पूर्व नियोजित था। डीजीपी ने कहा कि साक्षर मुख्यमंत्री कोनाहद सप्तामा को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई थी।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सभी साक्षरकर्तव्यों को निगरानत कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पटना में क्विंट सलियांता के उद्देशे विश्की गुणवत्त कोसत (टीएमपी) के नाती रुचद एच. मार्क सलियां से कम 19 लोगों को निगरानत किया गया है। उन्होंने बताया कि पटनायांती के अरणाजी की घटना के पीछेकी फुटन की मरद से कम 26 लोगों की पहचान की गई है।

खुफिया जासूसी से यह संकेत मिला है कि भीगे ने पक्षर और बोलत को मुख्यमंत्री के निर पर पक्षर उनको हत्या करने की साजिश रची थी। तुमूलु नेता ने मुख्यमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए भीगे को उकसाया था और हेला और जैसे अधिवायत कथन उठाने के लिए भीगे को भड़काने का काम किया था।

उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग समाप्त, अब 'सेतु' करेगा काम

जन्सता संवाददाता देहरादून, 25 जुलाई।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब समाप्त उत्तराखंड बनने के लिए 'सेतु' की नीति आयोग की तर्ज पर सेतु का निर्माण किया गया है, इसके लिए उत्तराखाल ने अपनी मंजूरी भी दी है। राज्य सरकार की कैबिनेट में योजना आयोग को समाप्त करके सेतु के गठन के लिए प्रस्ताव पेशित कर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब सेतु के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सेतु का पूरा नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंप्रूवमेंट एंड टूरिजमनिर्माण उत्तराखंड (सेतु) है। इसके गठन के लिए साक्षर अब मनीषा सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रमुख सरकारी की नीति व नियोजन में विचारकों की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री शीमा, सहाी निदेशक मनीष सुंदरम और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब समाप्त उत्तराखंड बनने के लिए 'सेतु' की नीति आयोग की तर्ज पर सेतु का निर्माण किया गया है, इसके लिए उत्तराखाल ने अपनी मंजूरी भी दी है। राज्य सरकार की कैबिनेट में योजना आयोग को समाप्त करके सेतु के गठन के लिए प्रस्ताव पेशित कर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।

'सेतु' का एम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंप्रूवमेंट एंड टूरिजमनिर्माण उत्तराखंड (सेतु)। इसके गठन के लिए साक्षर अब मनीषा सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

सेतु प्रमुख सरकारी की नीति व नियोजन में विचारकों की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री शीमा, सहाी निदेशक मनीष सुंदरम और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभु बजाज से विचार जाएगा। यह नाम अर्थशास्त्री था सेवानिवृत्त नीकरसाहब हो सकता है। सभी मंत्री इसके सदस्य होंगे। सेतु के तहत तीन केंद्र होंगे और प्रत्येक में दो-दो सलाहकार होंगे।

INVITATION TO THE RESIDUAL SHAREHOLDERS TO AVAIL THE EXIT OPPORTUNITY UNDER THE EXIT OFFER DFM FOODS LIMITED

Dear Residual Shareholder, This invitation dated July 25, 2023 to Residual Shareholder of the Company ('Exit Offer Advertisement') is being issued by JM Financial Limited ('Manager' or 'Manager to the Offer') for and on behalf of Global Investments (Private) PCC Limited ('Acquirer') along with All India (Capita) Limited ('PAC'), in accordance with Regulation 27(1)(a) and all other applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ('Delisting Regulations'). This Exit Offer Advertisement shall be read in conjunction of and shall be read in conjunction with and all capitalized terms used in this public information have the same meaning as ascribed to it in the initial public announcement dated August 15, 2022 ('IPA'), the detailed public announcement dated December 03, 2022 and published on December 03, 2022 ('Detailed Public Announcement') in (i) Financial Express (English, all editions), (ii) Jansatta (Hindi, all editions), (iii) Navshakti (Marathi, assembled edition) (collectively, the 'Newspapers'), the letter of offer dated December 05, 2022 ('Letter of Offer'), the post offer public announcement cum public announcement for counter offer dated December 20, 2022 and published in the Newspapers on December 21, 2022 ('Post Offer PA cum PA for Counter Offer'), the counter offer public announcement dated December 22, 2022 and published in the Newspapers on December 23, 2022 ('Counter Offer PA'), the counter offer letter of offer dated December 22, 2022 ('Counter Offer Letter of Offer'), the post offer public announcement dated January 11, 2023 and published on January 12, 2023 in the Newspapers ('Post Offer PA'), the Exit Offer Public Announcement dated March 16, 2023 and published on March 17, 2023 in the Newspapers ('Exit Offer PA') and the Exit Offer Public Announcement dated July 25, 2023 ('NSE Date of Delisting').

BSE Limited ('BSE') vide its notice number 20230314 dated March 14, 2023 ('BSE Final Delisting Approval') has communicated that trading in the Equity Shares of the Company (Scrip Code: 519588) will be discontinued with effect from March 28, 2023 ('BSE Date of Discontinuation of Trading') and the Company scrip will be delisted from BSE with effect from April 5, 2023 ('BSE Date of Delisting'). National Stock Exchange of India Limited ('NSE') vide its circular reference number 03/19/2023 dated March 14, 2023 ('NSE Final Delisting Approval'), has communicated that the security, DFM Foods Limited (Scrip Code: DFMFOODS) has been suspended from trading with effect from March 28, 2023 (i.e. with effect from closing hours of trading on March 27, 2023) ('NSE Date of Discontinuation of Trading') and further the admission to dealings in security, DFM Foods Limited shall be withdrawn (delisted) from NSE with effect from April 05, 2023 ('NSE Date of Delisting'). Delisting of the Equity Shares means that they cannot be traded on the Stock Exchanges and/or any other stock exchange and a liquid market for trading of the Equity Shares will no longer be available.

- 1. In terms of Regulation 27(1)(a) and all other applicable regulations of the Delisting Regulations, the Acquirer and PAC are inviting the Residual Shareholders to avail the exit opportunity during the one-year exit window after delisting of Equity Shares.
2. Exit Offer LOF has been dispatched to all the Residual Shareholders of the Company by the Acquirer, whose names appear in the records of the registrar of the Company and to the owners of Equity Shares whose names appear as beneficiaries on the records of the respective depositories (as the case may be) at the close of business hours as on March 28, 2023.
3. Residual Shareholders who have still not received their Equity Shares, can tender their Equity Shares to the Acquirer at the Exit Offer of INR 48/- during the Exit Window, i.e. from April 5, 2023 to April 4, 2024 (both dates inclusive), subject to the terms and conditions provided in Exit LOF. The Residual Shareholders are requested to ensure that they apply Application Form, together with the necessary enclosures (as mentioned in Exit LOF), is received by the Registrar to the Delisting Offer on or before April 04, 2024.
If the Residual Shareholders do not receive or misplaced the Exit LOF, they may obtain a copy of the Exit LOF by writing to the Registrar to the Delisting Offer, Link India Private Limited at C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India, clearly marking the envelope "DFM FOODS LIMITED DELISTING - EXIT OFFER" or e-mailing at dfmfoods.delisting@linkindia.com. Further, a soft copy of the Exit LOF may be downloaded from the website of the Registrar to the Delisting Offer at www.linkindia.com/indirect-downloads.html or the website of the Company at www.dfmsfoods.com
PAYMENT OF CONSIDERATION TO THE RESIDUAL SHAREHOLDERS
Subject to fulfillment of the terms and conditions mentioned in the Exit LOF, the Acquirer shall make payment on a monthly basis within 10 working days after the 21st calendar day of the relevant calendar month ('Monthly Payment Cycle'). Payment will be made only to those Residual Shareholders who have validly tendered their Equity Shares by following the instructions set out in the Exit LOF and receipt of formal Equity Shares in Special Depository Account (as defined in Exit LOF) or receipt of physical share certificates (along with duly filed transfer deeds and Exit Application Form) by Registrar to the Delisting Offer. Please note that the Acquirer reserves the right to make the payment early.
If the shareholders have any query with regard to the Exit Offer, they should contact the Manager to the Offer or the Registrar to the Delisting Offer (details appearing below). At all other terms and conditions of the Delisting Offer as set forth in the IPA, Detailed Public Announcement, Letter of Offer, Post Offer PA cum PA for Counter Offer, Counter Offer PA, Counter Offer Letter of Offer, the Post Offer PA, Exit Offer PA and the Exit LOF remain unchanged.

Table with 2 columns: MANAGER TO THE OFFER (JM FINANCIAL) and REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER (LINK Intime). Includes contact details for JM Financial and Link Intime.

RattanIndia Power Limited Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30 June 2023

Table showing financial results for RattanIndia Power Limited for the quarter ended 30 June 2023. Columns include Sr. No., Particulars, Quarter ended (30.06.2023, 31.03.2023, 30.06.2022, 31.03.2022), and Year ended (31.03.2023, 31.03.2022).

(b) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the unaudited financial results are available on the company's website www.rattanindiapower.com and on the Stock Exchanges website www.bseindia.com or www.nseindia.com.
(c) The Auditors in their Auditor's Report on Standalone Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below:
Sinnar Thermal Power Limited (STPL), is yet to commence operations and has incurred net loss amounting to Rs. 592.65 crores during the quarter ended 30 June 2023. As further explained in the note, the management has assessed that the STPL is stating a going concern for the purpose of accounting to appropriate basis the steps being undertaken. Further, STPL's accumulated losses as at 30 June 2023 amount to Rs. 12,396.53 crores and its current liabilities exceed its current assets by Rs. 16,977.28 crores.
Also, STPL has defaulted in repayment of borrowings from banks and financial institutions, including interest, aggregating to Rs. 12,476.84 crores up to 30 June 2023. As described in the said note, the Company's other current financial liabilities as at 30 June 2023 include balances amounting to Rs. 5,056.47 crores, in respect of which confirmations from the respective lenders have not been received while in case of certain lenders, the balance of borrowings and accrued interest confirmed as compared to balance as per books is higher by Rs. 347.87 crores and Rs. 318.36 crores respectively. In management's view, the subsidiary company has secured for all the dues payable to the lenders in accordance with the terms of the respective loan agreements/sanction letters and carrying value of assets is recoverable as on 30 June 2023.
The Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi (NCLT) vide order dated 19 September 2022, admitted an application for insolvency filed by an operational creditor (STPL) and initiated Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ('IBC'). However, subsequently, in response to the appeal filed against the NCLT order, the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) vide its order dated 26 September 2022 had directed the Interim Resolution Professional ('the IRP') to abstain from taking any steps and has allowed STPL to participate further with the Ministry of Power in continuation of the earlier meetings/discussions for making the plant operational, as detailed in the aforesaid note.
In view of significant uncertainties associated with the outcome of CIRP proceedings and the outcome of ongoing discussions with the lenders for settlement of dues and to secure firm and unconditional confirmation for providing working capital loans/bank guarantees required for executing the power purchase agreement (PPA) required to commence operations and the non-receipt of balance confirmations from the lenders or sufficient and appropriate alternate audit evidence to support the management's assessment as mentioned above, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on the appropriateness of going concern assessment of STPL, its management and/or adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of assets including plant and equipment of STPL. Aggregating to Rs. 6,838.64 crores and the liabilities aggregating to Rs. 6,592.80 crores as at 30 June 2023, included in the Group's consolidated financial results and the consequential impact thereof on the accompanying consolidated financial results for the quarter ended 30 June 2023.
(d) The Auditors in their Auditor's Report on Standalone Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below:
The Company has non-current investment of Rs. 1,211.82 crores (net of impairment provision of Rs. 1,814.39 crores) and inter-corporate deposit (classified under current assets) of Rs. 34.00 crores recoverable from Sinnar Thermal Power Limited (formerly RattanIndia Naxa Power Limited) (STPL). STPL has incurred losses since its inception and is yet to commence operations. As further explained in the aforesaid note, management has assessed that the STPL is stating a going concern for the purpose of accounting to appropriate basis the steps being undertaken. Further, the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi (NCLT) vide order dated 19 September 2022, admitted an application for insolvency filed by an operational creditor (STPL) and initiated Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ('IBC'). However, subsequently, in response to the appeal filed against the NCLT order, the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) vide its order dated 26 September 2022 had directed the Interim Resolution Professional ('the IRP') to abstain from taking any steps and has allowed STPL to participate further with the Ministry of Power in continuation of the earlier meetings/discussions for making the plant operational, as detailed in the aforesaid note.
In view of significant uncertainties associated with the outcome of CIRP proceedings and in the absence of adequate evidence to support the appropriateness of going concern assessment of STPL, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to comment on adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of the above mentioned non-current investment of Rs. 1,211.82 crores and inter-corporate deposit of Rs. 34.00 crores as at 30 June 2023 and the consequential impact thereon on the accompanying Statement for the quarter ended 30 June 2023.

नियुक्तियां जनता का पूर्ण समर्थन : अरुण कुमार

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India प्रतिक्रियात्मक अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)
1931 से जन्म लेने वाला 'सेंट्रल' 'CENTRAL' TO YOU SINCE 1931
शाखा कार्यवाही: 59, पंडितलाला विहिना, नेहरू प्लेन, नई दिल्ली-110019
वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हिता सर्वधन (सफेकी) अधिनियम, 2002 की मांग 13(2) के तहत कर्जदार को नाम सूचना।

मेगलिया का चुनाव को मिलेगा जनता का पूर्ण समर्थन : अरुण कुमार

जन्सता ब्यूरो नई दिल्ली, 25 जुलाई।
विश्वी गठबंधन पर बिहार के जहानवाहा से पूर्व संसद अरुण कुमार ने निशा साधा है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं, जिनमें कई विधायी पर वैचारिक मतभेद हैं। बिहार की राजनीति में एक दुसरे के विरोधी भी नतीश और मजगुदर अथक साथ हैं। बिहार के नीतियां हाकालत के नीचे नहीं पाट्टियां के एक साथ होने की बात प्रचुर के अलावा समझ रही हैं। इसके खिलाफ अरुण को लोकसभा चुनाव में बिहार में पूरा समर्थन देने का सूत्र संसद ने बना लिया।
मुत्तल संसद सभा पाट्टी की प्रतिभूतिकरण अरुण कुमार ने संसदलालाओं से बातचीत में कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां एकमत नहीं हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India प्रतिक्रियात्मक अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)
1931 से जन्म लेने वाला 'सेंट्रल' 'CENTRAL' TO YOU SINCE 1931
शाखा कार्यवाही: 59, पंडितलाला विहिना, नेहरू प्लेन, नई दिल्ली-110019
वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हिता सर्वधन (सफेकी) अधिनियम, 2002 की मांग 13(2) के तहत कर्जदार को नाम सूचना।
वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हिता सर्वधन (सफेकी) अधिनियम, 2002 की मांग 13(2) के तहत कर्जदार को नाम सूचना।
वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हिता सर्वधन (सफेकी) अधिनियम, 2002 की मांग 13(2) के तहत कर्जदार को नाम सूचना।

मेगलिया का चुनाव को मिलेगा जनता का पूर्ण समर्थन : अरुण कुमार

जन्सता ब्यूरो नई दिल्ली, 25 जुलाई।
विश्वी गठबंधन पर बिहार के जहानवाहा से पूर्व संसद अरुण कुमार ने निशा साधा है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं, जिनमें कई विधायी पर वैचारिक मतभेद हैं। बिहार की राजनीति में एक दुसरे के विरोधी भी नतीश और मजगुदर अथक साथ हैं। बिहार के नीतियां हाकालत के नीचे नहीं पाट्टियां के एक साथ होने की बात प्रचुर के अलावा समझ रही हैं। इसके खिलाफ अरुण को लोकसभा चुनाव में बिहार में पूरा समर्थन देने का सूत्र संसद ने बना लिया।
मुत्तल संसद सभा पाट्टी की प्रतिभूतिकरण अरुण कुमार ने संसदलालाओं से बातचीत में कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां एकमत नहीं हैं।

मेगलिया का चुनाव को मिलेगा जनता का पूर्ण समर्थन : अरुण कुमार

जन्सता ब्यूरो नई दिल्ली, 25 जुलाई।
विश्वी गठबंधन पर बिहार के जहानवाहा से पूर्व संसद अरुण कुमार ने निशा साधा है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं, जिनमें कई विधायी पर वैचारिक मतभेद हैं। बिहार की राजनीति में एक दुसरे के विरोधी भी नतीश और मजगुदर अथक साथ हैं। बिहार के नीतियां हाकालत के नीचे नहीं पाट्टियां के एक साथ होने की बात प्रचुर के अलावा समझ रही हैं। इसके खिलाफ अरुण को लोकसभा चुनाव में बिहार में पूरा समर्थन देने का सूत्र संसद ने बना लिया।
मुत्तल संसद सभा पाट्टी की प्रतिभूतिकरण अरुण कुमार ने संसदलालाओं से बातचीत में कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां एकमत नहीं हैं।

मेगलिया का चुनाव को मिलेगा जनता का पूर्ण समर्थन : अरुण कुमार

जन्सता ब्यूरो नई दिल्ली, 25 जुलाई।
विश्वी गठबंधन पर बिहार के जहानवाहा से पूर्व संसद अरुण कुमार ने निशा साधा है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं, जिनमें कई विधायी पर वैचारिक मतभेद हैं। बिहार की राजनीति में एक दुसरे के विरोधी भी नतीश और मजगुदर अथक साथ हैं। बिहार के नीतियां हाकालत के नीचे नहीं पाट्टियां के एक साथ होने की बात प्रचुर के अलावा समझ रही हैं। इसके खिलाफ अरुण को लोकसभा चुनाव में बिहार में पूरा समर्थन देने का सूत्र संसद ने बना लिया।
मुत्तल संसद सभा पाट्टी की प्रतिभूतिकरण अरुण कुमार ने संसदलालाओं से बातचीत में कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां एकमत नहीं हैं।

जन्सता ब्यूरो नई दिल्ली, 25 जुलाई।
विश्वी गठबंधन पर बिहार के जहानवाहा से पूर्व संसद अरुण कुमार ने निशा साधा है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं, जिनमें कई विधायी पर वैचारिक मतभेद हैं। बिहार की राजनीति में एक दुसरे के विरोधी भी नतीश और मजगुदर अथक साथ हैं। बिहार के नीतियां हाकालत के नीचे नहीं पाट्टियां के एक साथ होने की बात प्रचुर के अलावा समझ रही हैं। इसके खिलाफ अरुण को लोकसभा चुनाव में बिहार में पूरा समर्थन देने का सूत्र संसद ने बना लिया।
मुत्तल संसद सभा पाट्टी की प्रतिभूतिकरण अरुण कुमार ने संसदलालाओं से बातचीत में कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां एकमत नहीं हैं।